नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

जबलपुर 77 वां वर्ष संस्करण

5 नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम कैसे

6 एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक वंदेमातरम्

7 इंडिगो की उड़ानों पर 10 प्रतिशत की कटौती

8 दिया-मानुष की जोड़ी करेगी भारत का प्रतिनिधित्व

बुंदेलखंड में सरकार

- बुंदेलखंड में निवेश पर स्टाम्प और पंजीयन शुल्क फ्री
- कैबिनेट निर्णय : सरकार करेगी शुल्क की भरपाई

05 वर्ष तक बिजली शुल्क से भी मिलेगी राहत | **24240** करोड़ रुपये के निवेश की राह होगी आसान

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 दिसंबर. बुंदेलखंड के विकास को नया पंख देने के लिये मंगलवार को बुंदेलखंड की धरती से ही राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय किया है. बुंदेलखंड में अब यदि कोई निवेश करता है तो उसे स्टाम्प और पंजीयन शुल्क नहीं देना पड़ेगा. इसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी. इतना ही नहीं पांच वर्ष तक बिजली शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा. इससे बुंदेलखंड में 24240 करोड़ रुपये के निवेश की राह खुलेगी.

खजुराहो में हुई कैबिनेट के दौरान सागर के औद्योगिक क्षेत्र मसवासी ग्रंट के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी गई है. इस पैकेज से क्षेत्र में 29 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा. यहां निवेश करने पर भूमि प्रब्याजी और वार्षिक भू-भाटक की दर केवल एक रुपये प्रति वर्गमीटर पर मिलेगा. इसके अलावा, विकास शुल्क चुकाने के लिए 20 समान वार्षिक किश्तों की सुविधा दी गई है और मेंटनेंस शुल्क महज 8 रुपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक तय किया गया है.

सीमेंट निर्माण इकाइयों को इस विशेष वित्तीय सहायता पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा .यह विशेष पैकेज अगले पांच वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा.

सागर से दमोह 76 किलोमीटर फोरलेन बनेगा: कैबिनेट ने सागर-दमोह मार्ग, लंबाई 76.680 किमी फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के साथ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एचएएम के तहत बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इस फोरलेन की लागत 2,059 करोड़ 85 लाख रूपए होगी. लागत का 40 फीसदी हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत मप्र सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से जीएसटी सहित वहन किया जाएगा बाकी शेष 60... (शेष पेज 7 पर)

यह निर्णय भी लिये

- पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को 2 वर्ष में रोजगार के लिए जापान और जर्मनी भेजा जाएगा.
- प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति.

3 मेडिकल कॉलेज के लिये आउटसोर्स पदों को मंजूरी

कैबिनेट ने नए मेडिकल कॉलेज दमोह, छतरपुर और बुधनी के संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउट सोर्स पदों की स्वीकृति दी गई है. स्वीकृति अनुसार प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में 330 नियमित पद सृजन और 205 व्यक्तियों को आउट सोर्स पर नियोजित किए जाने की मंजूरी दी है.

11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन होगा

कैबिनेट ने 11 जिलों की 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है. निर्णय अनुसार नीमच जिले के भादवामाता उप स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया जाएगा. शाजापुर के मक्सी स्थित 6 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य... (शेष पेज 07 पर

कांग्रेस के खून में है वंदे मातरम् का विरोध

- राज्यसभा में कांग्रेस पर बरसे गृहमंत्री अमित शाह
- राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् पर राज्यसभा में चर्चा

नई दिल्ली, 9 दिसंबर. राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् पर लोकसभा में सोमवार को हुई चर्चा के बाद आज बारी थी राज्यसभा की. राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए वंदे मातरम को देश भक्ति, त्याग और राष्ट्र चेतना का प्रतीक बताया और कहा जो लोग इस समय इसकी चर्चा करने के औचित्य और जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपनी सोच पर नये सिरे से विचार करना चाहिए.

शाह ने संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि वंदे मातरम के 100 साल पूरे होने पर पूरे देश को बंदी बनाया गया था. इसके बाद जब वंदे मातरम के 150 साल पर सदन (लोकसभा) में चर्चा शुरू हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य (राहुल-प्रियंका) नदारद थे. वंदे मातरम् का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है।

शाह ने उम्मीद जताई कि इस चर्चा के माध्यम से देश के बच्चे, युवा और आने वाली पीढ़ी यह बात समझ सकेगी कि वंदे मातरम् का देश का आजादी दिलाने में क्या योगदान रहा है. उन्होंने कहा कि लोकसभा में इस विषय पर कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम् पर चर्चा क्यों होनी चाहिए। शाह ने कहा, भारत माता की जो संतानें हैं, वे मानते हैं कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसे हम अपनी मां मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं. यह भक्ति गान ही वंदे मातरम है. वंदे मातरम ने हमारे जीवन में भारत माता की कल्पना का जो योगदान है, उसे बहुत अच्छे से भावना के साथ बताया है. लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का जो स्वरूप है, वह भारत माता है. हमारा ज्ञान, विज्ञान सब भारत माता की ही कृपा है और भारत माता की प्रार्थना से ही साकार हो सकता है.

आरएसएस और बीजेपी का देश की संस्थाओं पर कब्जा : राहुल

राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधार (एसआईआर) पर 28 मिनट की स्पीच दी. कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही हैं. इनमें चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शामिल हैं. इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव आयोग को कंट्रोल और निर्देशित (डायरेक्ट) कर रही है. इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है. राहुल की स्पीच के दौरान 5 बार हंगामा हुआ, क्योंकि राहुल चुनाव सुधार के बदले आरएसएस सहित अन्य विषयों पर बोलने लगे. इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस को समानता से दिक्कत है. चुनाव सुधार पर चल रही बहस में राहुल गांधी ने खादी, महात्मा गांधी, गोडसे, आरएसएस का भी जिक्र किया. संसद का निचला सदन चुनाव सुधारों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. इसमें भारत के चुनाव आयोग द्वारा अलग-अलग राज्यों में शुरू किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज पर चर्चा शामिल है. विपक्षी पार्टियां महीनों से एसआईआर पर बहस की मांग कर रही हैं, कांग्रेस वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगा रही है.

देश अब पूरी तरह से 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' फेज में

नई दिल्ली, 9 दिसंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संसदीय दल के नेताओं से कहा कि भारत पूरी तरह से रिफॉर्म एक्सप्रेस चरण में आ गया है, जिसमें तेज और नागरिकों केंद्रित शासन बदलाव होंगे।

सांसदों को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सिर्फ आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने या रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी को असल में आसान बनाने के लिए रिफॉर्म कर रही है. उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य नागरिकों के सामने आने वाली रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर करना है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें.

एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में मोदी का सम्मान

दो दोस्तों को मिला 50 लाख का हीरा

पन्ना. आज फिर दो दोस्त एक माह के अंदर लखपति बन गए. हीरा खदान संचालक सतीष खटीक एवं साजिद मोहम्मद दो लोगों ने एक साथ मिलकर कृष्णा कल्याणपुर में हीरा की खदान 19 नवंबर को स्वीकृत कराई थी. 19 नवंबर से 31 दिसंबर तक के लिए हीरा खदान का पट्टा दिया गया. सोमवार को उन्हें 15.34 कैरेट का जैम क्वालिटी का हीरा मिला, जिसकी बाजारू कीमत 50 लाख से भी अधिक बताई जा रही है. फिलहाल हीरे को कार्यालय में जमा किया गया है.

वाधवानी को 2002 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस

नव भारत न्यूज

इंदौर, 9 दिसंबर. करीब पांच साल से चल रही कानूनी रस्साकशी और जांच के बाद सेंट्रल जीएसटी एंड एक्साइज कमिश्नरेट ने शहर के बहुचर्चित गुटखा कारोबारी नेटवर्क पर अब तक का सबसे बड़ा वार कर दिया है.

विभाग ने किशोर वाधवानी सहित उससे जुड़े कारोबारियों और फर्मों को 2002 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड थमा दी है. माना जा रहा है कि यह प्रदेश में जारी हुआ अब तक का सबसे बड़ा टैक्स डिमांड नोटिस है.

यह कार्रवाई उसी प्रकरण से जुड़ी है, जिसमें 2020 में बड़े पैमाने पर छापे पड़े थे. जांच में सामने आया कि 2017 से 2020 के बीच व्यवस्थित तरीके से टैक्स चोरी की... (शेष पेज 7 पर)

जांच में ऐसे खुला घोटाला

छापों के बाद विभाग ने जुलाई 2017 से जून 2020 के बीच की टैक्स चोरी का पूरा ग्राफ तैयार किया था, इसमें 1-17 जुलाई 2017 : 24.08 करोड़, 18 जुलाई 2017-6 जुलाई 2019 : 1345.73 करोड़, जुलाई 2019-1 फरवरी 2020 : 418.78 करोड़, 2 फरवरी-10 जून 2020 : 157.63 करोड़, कुल टैक्स चोरी 1946.23 करोड़ और अलग से 75.67 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी जोड़कर डिमांड 2002 करोड़ तय की गई.

फूड प्वाइजनिंग से 3 की मौत, 5 कर्मचारी बीमार

ग्वालियर. फूड प्वॉइजनिंग का गंभीर मामला सामने आया है, जहां खजुराहो के गौतम रिसॉर्ट के आठ कर्मचारियों की हालत अचानक बिगड़ गई. इनमें से तीन की मौत हो गई. बीती रात रिसॉर्ट में परोसी गई आलू-गोभी की सब्जी खाने के बाद कर्मचारियों को उल्टी-दस्त और तेज पेट दर्द की शिकायत होने लगी. हालत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल खजुराहो के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

सरकार ने 10 बड़े एयरपोर्ट पर आईएएस भेजे

नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में 8 दिन संकट बरकरार है. इस बीच सरकार ने इंडिगो पर भी सख्त एक्शन लिया है. सोमवार को सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग हुई. केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात किया है. ये लोग पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन-कौन सी परेशानी आ रही है. ये अफसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं. 10 बड़े एयरपोर्ट में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं.

इंडिगो को रूट में 10 प्रतिशत कटौती का आदेश

सरकार ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने वाली विमान सेवा कंपनी इंडिगो को उसके रूट में 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने मंगलवार को इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एलबर्स को तलब किया था।

हालात से निपटें वरना अराजकता फैल जाएगी : सीजेआई

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने चुनाव आयोग और ममता सरकार को नोटिस जारी किया. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता सनातन संसद ने राज्य में एसआईआर के कामकाज की अवधि के दौरान बीएलओ के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की मांग भी की और याचिका में घर-घर सत्यापन करने वाले बीएलओ पर कथित हमलों का हवाला दिया गया है. उन्होंने अदालत से कहा कि पश्चिम बंगाल में बीएलओ को एसआईआर ड्यूटी करते समय हिंसा का सामना करना पड़ रहा है.